www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 177 | जौनपुर बुधवार, 11 फरवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

महिला, युवा, गरीब के विकास को केंद्रित होगा बजट : सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। योगी आदित्यनाथ की सरकार बुधवार 11 फरवरी को अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करेगी। विधानसभा चुनावों से पहले का अंतिम बजट होने के कारण माना जा रहा है कि सरकार इस बार महिलाओं–युवाओं को लुभाने वाला आकर्षक लोकलुभावन बजट पेश कर सकती है। अब तक के कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य के मूलभूत ढांचे में भारी निवेश कर प्रदेश के विकास की गति बढ़ाई है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोले हैं। अपराध से मुक्त प्रदेश का वातावरण देकर योगी सरकार ने देश–विदेश के पूंजीपतियों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित किया है

जिससे यूपी बीमारू राज्यों से बाहर निकलकर सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। बजट 2026–27 में सरकार विकास के अपने इस मूल मंत्र को बनाए रखने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, विपक्ष ने सरकार पर पिछली योजनाओं में असफल रहने का आरोप लगाया है। हालांकि, अंतिम बजट होने के कारण माना जा रहा है कि सरकार अपने विशेष समर्थक वर्ग को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा भी कर सकती है। इसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं में मानदेय बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। किसानों का मुद्दा राज्य में प्रमुख विषय बना हुआ है। सरकार किसानों को साथ लेने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा कर सकती है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी सरकार पर्यटन में निवेश बढ़ाकर रोजगार के निर्माण पर ध्यान देगी। वह पर्यावरण में निवेश को बढ़ाकर राज्य के वातावरण को बेहतर करने की कोशिश कर सकती है। इसके लिए ई वाहनों, सौर ऊर्जा में बजट बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, यूपी के स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर अपने कामगरों को सशक्त कर राज्य को विकसित करने का खाका पेश किया जा सकता है। बजट से पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वे में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 30 लाख करोड़ के पार होने की बात कही गई है।

संसद में टकराव टलना मुश्किल, कार्यवाही चलाने को लेकर शर्तों पर फंसा पेंच

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लोकसभा की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने का मामला शर्त बनाम शर्त में उलझ गया है। इसकी वजह से संकेत हैं कि बजट सत्र का पहला चरण हंगामे में ही कटेगा। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन के सुचारु संचालन के लिए बजट पर चर्चा से पहले भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता पर संक्षिप्त चर्चा की शर्त रखी। इसके जवाब में सरकार ने उनसे सत्र के दौरान सदन में हुई घटनाओं पर खेद जताने की शर्त रखी है। बजट सत्र के दौरान अप्रकाशित किताब, सांसदों के निलंबन, विपक्षी महिला सांसदों पर पीएम पर हमले की साजिश जैसे मुद्दे ने सरकार और विपक्ष के संबंधों की खाई चौड़ी कर दी है। इससे पहले, राहुल गांधी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ लोकसभा अध्यक्ष के साथ सोमवार को आधे घंटे बैठक की। इसके बाद गतिरोध दूर होने की उम्मीद जगी थी। नेता प्रतिपक्ष ने बजट पर चर्चा से पूर्व व्यापार समझौते पर संक्षिप्त चर्चा और इसकी शुरुआत

उनकी ओर से शुरू करने की शर्त रखी। इसके जवाब में सरकार ने शर्त रखा कि सत्र के दौरान आसन, प्रधानमंत्री की अवमानना, सदन में विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर नेता प्रतिपक्ष खेद जताएं। सरकारी सूत्रों ने कहा, यह भी हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष भारत–अमेरिका समझौते पर बोलने के बाद फिर से सदन की कार्यवाही न चलने दें। ऐसे में सरकार किसी शर्त के बंधन में नहीं बंधना चाहती। राहुल ने सोमवार शाम को दावा किया कि अध्यक्ष ने उन्हें बजट सत्र पर चर्चा से पहले बोलने देने का आश्वासन दिया है।

संक्षिप्त खबरें

'भाजपा के भगवान राम नहीं, ओवैसी', तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा हमला

हैदराबाद, (एजेंसी)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेते हुए भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। नगरपालिका चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के भगवान राम नहीं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी हैं। एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की जीवनरेखा है, वे उनके नाम पर वोट मांगते हैं। सीएम रेवंत रेड्डी का भाजपा पर ये अब तक बड़ा हमला माना जा रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भाजपा पर बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो नेता भगवान राम का नाम जपने का दावा करते हैं, वे राजनीतिक फायदे के लिए बार–बार एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेने में लगे रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ओवैसी को 'राजनीतिक डरावने पुतले' के तौर पर इस्तेमाल कर रही है ताकि वोटरों को बांटा जा सके और सांप्रदायिक नफरत फैलाई जा सके। उन्होंने इसे भाजपा का वैचारिक दिवालियापन बताया है। मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं की आलोचना करते हुए कहा जब हैदराबाद में बाढ़ आई थी, तब बांदी संजय कुमार ने वादा किया था कि लोगों के खोए सामान की भरपाई होगी। बाद में उन्होंने कहा कि क्योंकि लोग बीमा करवा चुके हैं, इसलिए वे स्वयं खरीद लें। अब वही लोग वोट मांग रहे हैं।

पवन खेड़ा ने एपस्टीन फाइल में दीया कुमारी और उनके बेटे का नाम जोड़ा

जयपुर, (एजेंसी)। जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों और कथित खुलासों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज है। इसी बीच भारत में भी इस मुद्दे ने सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और उनके पुत्र सवाई पद्मनाभ सिंह का नाम एपस्टीन फाइल्स से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं। भाजपा ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित और तथ्यहीन बताया है। राजस्थान विधानसभा में 11 फरवरी को बजट 2026 पेश होना है। उससे पहले खेड़ा के बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि 14 मई 2018 को एक अज्ञात प्रेषक ने जेफ्री एपस्टीन को ईमेल भेजा था, जिसमें लिखा गया था कि रोम के पास स्थित पारिवारिक किले में "जयपुर के महाराजा" का जन्मदिन समारोह आयोजित किया जा रहा है। खेड़ा ने इस संदर्भ को सवाई पद्मनाभ सिंह से जोड़ते हुए कहा कि 2018 में रोम में उनका 20वां जन्मदिन समारोह सार्वजनिक रूप से चर्चा में रहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उस आयोजन का संबंध एपस्टीन या उसके सहयोगियों से था। खेड़ा ने अपने पोस्ट में लिखा ।

राहुल गांधी के लिए कांग्रेस ने गिराई सदन की गरिमा : रिजिजू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मंगलवार को विपक्षी सांसदों द्वारा सदन के वेल में विरोध प्रदर्शन करने के बाद लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया। निचले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने के तुरंत बाद दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी

गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में हंगामा करने और कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। रिजिजू ने दावा किया कि कई विपक्षी दल केंद्रीय बजट 2026–27 पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस संसद को चलने नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि आज बजट का समय है, और हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैंने कल भी कांग्रेस से इस पर चर्चा करने को कहा था। डीएमके, समाजवादी पार्टी और तृणमूल के नेता बोलने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस संसद को चलने नहीं देना चाहती। रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया कि मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने सदन की गरिमा को पहले ही बहुत गिरा दिया है, और अब इसे और गिरने न दें। बजट पर चर्चा होने दें। किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि बजट पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। वे हर रोज सदन में आकर हंगामा करते हैं। कांग्रेस पार्टी पहले ही संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा चुकी है।

शरद पवार की सेहत में सुधार, पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने फोन कर जाना हालचाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सोमवार को सीने में जकड़न की शिकायत पर पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है और सभी वाइटल पैरामीटर सामान्य हैं। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर उनका हालचाल जाना। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार की सेहत में अब पहले से सुधार आया है। सोमवार को उन्हें सीने में जकड़न की शिकायत के बाद पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और सभी वाइटल

पैरामीटर सामान्य हैं। ऐसे में आज यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से फोन पर बात की और उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली। सूत्रों के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनसे फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना। बता दें कि शरद पवार को पुणे के रूबी हॉल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें एंटीबायोटिक्स देने की योजना बनाई है, जो अगले चार दिन जारी रहेगी। उन्हें फिलहाल आराम करने और किसी से मिलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों ने बताया कि पवार का सीटी स्कैन किया गया, जिसमें छाती में संक्रमण पाया गया। उनका हृदय और ऑक्सीजन स्तर सामान्य हैं। हालांकि, सांस लेने की दर थोड़ी बढ़ी हुई है। उनका इलाज सामान्य वार्ड में किया जा रहा है और उन्हें आईसीयू में नहीं रखा गया है। अस्पताल में उनके कई मेडिकल टेस्ट किए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक, सीटी स्कैन में छाती में संक्रमण पाया गया है। हालांकि उनकी ऑक्सीजन लेवल और दिल की धड़कन सामान्य है। उनका इलाज सामान्य वार्ड में चल रहा है और उन्हें आईसीयू में नहीं रखा गया है। इलाज कर रहे डॉक्टर अभिजीत लोढ़ा ने बताया कि ज्यादा शारीरिक थकान के कारण उन्हें खांसी और सीने में जकड़न हुई। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और सभी जरूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद इलाज में बदलाव किया जाएगा।

असम सीएम हिमंत सरमा ने गोगोई पर ठोका 500 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा

गुवाहाटी, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आरोप उनकी छवि खराब करने के इरादे से लगाए गए हैं। इन आरोपों के खिलाफ मुख्यमंत्री सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और दो अन्य लोगों के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का मानहानि (डिफेमेशन) का केस दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने बिना किसी सबूत के गंभीर आरोप लगाए, जिससे उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने साफ कहा कि वह इस मामले में कानूनी रास्ते से जवाब देंगे। सरमा ने कहा कि

राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन झूठे आरोप लगाना गलत है। इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को असम कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस विधायक शिबामोनी बोरा और दिगंत बर्मन ने गुवाहाटी के दिसपुर पुलिस स्टेशन में इस वीडियो को लेकर शिकायत दी। इस वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को एक राइफल के साथ दिखाया गया था। वीडियो शेयर करते ही इस पर विवाद खड़ा हो गया। हालांकि विवाद बढ़ता देख इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि वीडियो में सरमा को एक विशेष समुदाय पर पॉइंट–ब्लैंक रेंज से गोली मारते दिखाया गया है। शिकायतकर्ता विधायकों ने दावा किया कि वीडियो में ओवरले टेक्स्ट के रूप में कुछ वाक्य थे जैसे– विदेशी मुक्त असम और बांग्लादेशियों को कोई माफी नहीं। कांग्रेस का कहना है कि ये शब्द राज्य के बंगाल मूल के मुसलमानों की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें अक्सर मिया या बांग्लादेशी कहकर तंज कसा जाता है। इसके साथ ही शिकायत में आगे कहा गया कि यह सामग्री एक खास समुदाय को निशाना बनाती है, जो बेहद उकसाने वाली और सांप्रदायिक है। इससे लोगों के बीच सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है।

राहुल गांधी लोकसभा में बोलने की जिद पर अड़े, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लोकसभा में आज भी हंगामा जारी है। राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब के कुछ अंश लोकसभा में पढ़ने की जिद पर अड़े हैं। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि या तो पेंगुइन प्रकाशन झूठ बोल रहा है या नरवणे जी झूठ बोल रहे हैं। उन्ह्होंने कहा कि मुझे पूर्व सेना प्रमुख के दावे पर विश्ध्वास है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी सांसद आज ही स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। हालांकि, 9 फरवरी को सूत्रों के हवाले से आई जानकारी में कहा गया था कि बजट सत्र के दूसरे चरण में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा।लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने आज भी स्पीकर

ओम बिरला को कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस समेत कई अन्य दलों के सांसदों ने स्पीकर से अहम मुद्दे पर चर्चा कराने की अपील की है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्यसभा में बजट 2026 पर चर्चा पूरी होने पर इसका जवाब दे सकती हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि सरकार को भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा करानी चाहिए।लोकसभा में आज बजट 2026 पर चर्चा होने की उम्मीद है। 9 फरवरी की कार्यवाही के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से सदन की कार्यवाही के संचालन में मदद करने की अपील की थी। हालांकि, पहले 11 बजे लोकसभा का प्रश्नकाल बाधित हुआ।

नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री, उम्र बढ़ने के साथ बीमारी भी बढ़ती है : तेजस्वी यादव

पटना, (एजेंसी)। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने नीतीश कुमार को कमजोर मुख्यमंत्री तक बता दिया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा , षबिहार में लगातार अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। खासकर छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की कई घटनाएं हो रही हैं। नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की मौत का मामला ठंडा ही नहीं हुआ कि दरभंगा में बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। कई जिलों से मामले सामने आए हैं। ष उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन सभी मामलों को लेकर राजद सरकार से सवाल कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस सवाल को सदन में भी उठाया। सरकार इन प्रश्नों का जवाब देने के बजाय जिस तरह की भाषा का उपयोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, वह सही नहीं है। ऐसी भाषा देखकर लोगों का मन और बढ़ता है। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि घटनाओं को रोकने और जवाब देने के बजाय सरकार को इस तरह की बातें करना किसी मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सही है। पूर्व महिला मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत और उम्र को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है और उम्र बढ़ने के साथ बीमारी आती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले विदेश जाकर इलाज करा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में मुख्यमंत्री का माइक बंद कर दिया जा रहा है। इससे पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर भी लिखा था, षडिमेंशिया और अल्जाइमर का दुष्प्रभाव जब बढ़ता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है, जहां आप सहानुभूतिपूर्वक रोगी के मानसिक स्वास्थ्य लाभ की कामना ही कर सकते हैं। प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री को श्लड़कीश कहने तथा महिलाओं के प्रति अपनी संकीर्ण, नकारात्मक और दोषपूर्ण सोच का बारंबार प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री को आप क्या कहेंगे?

फैसला राज्य सरकार का, केंद्र की भूमिका नहीं : शिवकुमार

बंगलूरू , (एजेंसी)। कर्नाटक में बंगलूरू मेट्रो के किराए को लेकर सियासी और प्रशासनिक टकराव तेज होता जा रहा है। किराया बढ़ोतरी पर रोक के दावों के बीच अब जिम्मेदारी तय करने को लेकर केंद्र और राज्य आमने–सामने हैं। ऐसे में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस पूरे मामले में कर्नाटक सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि बंगलूरू मेट्रो के किराए में प्रस्तावित बढ़ोतरी को रोकने का फैसला राज्य सरकार ने खुद लिया है, इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र का इस मामले में न तो कोई अधिकार है और न ही दखल देने का कानूनी आधार। कर्नाटक विधान सौधा में प्रेस वार्चा के दौरान शिवकुमार ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों

में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया पत्र कानूनी रूप से कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किराए से जुड़े आंकड़ों को दोबारा जांचा जाए और तब तक किराया बढ़ोतरी को रोका जाए। डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें लगा था कि इस मुद्दे पर दिल्ली में बैठक होगी, लेकिन वह भी टल गई। जो लोग इस पर जीत का दावा कर रहे हैं, उन्हें पहले बैठक सुनिश्चित करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में हकीकत से ज्यादा राजनीति हो रही है। इसके साथ ही किराया निर्धारण समिति को लेकर उन्होंने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे केंद्र सरकार किराया रोकने का निर्देश दे सके। अगर कोई नया फैसला लेना है तो नई किराया निर्धारण समिति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि वे जनता की आवाज बनने के लिए काम कर रहे हैं। डीके शिवकुमार ने बताया कि मौजूदा किराया बढ़ोतरी का फैसला एक साल पहले बनी पुरानी किराया निर्धारण समिति ने लिया था। राज्य सरकार ने न तो किराया बढ़ाने को कहा था और न ही इस पर कोई निर्देश दिए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब फैसला हुआ था, तब आज बयान देने वाले नेता चुप क्यों थे। भाजपा नेताओं द्वारा किराया बढ़ोतरी रुकवाने का श्रेय लेने पर उन्होंने कहा कि कोई भी श्रेय ले ले, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनका मकसद सिर्फ यह है कि न तो जनता पर बोझ पड़े और न ही मेट्रो को नुकसान हो। उन्होंने कहा कि वे किसी दबाव में काम नहीं कर रहे हैं।

संपादकीय

भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए नुकसान का पहलू

अमेरिका में टैरिफ 18 प्रतिशत होने से भारत के श्रम–केंद्रित उद्योगों को राहत मिलेगी। लेकिन अमेरिका की भू–राजनीतिक रणनीतियों से जुड़ी शर्तें डील में शामिल हुईं, तो आर्थिक के साथ–साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए भी वो हानिकारक बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने अपने चिर–परिचित अंदाज में भारत से ट्रेड डील होने का एलान किया। कहा कि इसके तहत अमेरिका भारत पर शलिबरेशन डे टैरिफ्य को 25 से घटा कर 18 प्रतिशत कर देगा। बदले में भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करेगा, अमेरिका से व्यापार में टैरिफ एवं गैर–टैरिफ रुकावटों को शून्य कर देगा, और 500 बिलियन डॉलर के ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला एवं अन्य उत्पाद खरीदेगा। 500 बिलियन डॉलर का अर्थ भारत के सालाना बजट का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा (तकरीबन 46 लाख करोड़ रुपये) है। बहरहाल, ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जारी अपने बयान में प्रधानमंत्री ने सिर्फ यह उल्लेख किया कि भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में अब सिर्फ 18 प्रतिशत आयात शुल्क लगेगा। इससे ट्रेड डील को लेकर फिर से अस्पष्टता बन गई। बहरहाल, यह साफ है कि इस डील को हासिल करने के लिए भारत ने आगे बढ़ कर कई बड़ी रियायतें दी हैं। उनमें से कई तो करार के पहले ही दे दी गईं। इनमें अमेरिका के कृषि, वाहन, सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, धातु एवं केमिकल्स उत्पादों पर भारत में आयात शुल्क में भारी कटौती शामिल है। साथ ही रक्षा सौदों का दायरा बढ़ाया गया। परमाणु उत्तरदायित्व कानून में अमेरिकी कंपनियों के अनुकूल बदलाव किया गया। ट्रंप प्रशासन के दबाव में भारत ने रूस से तेल की खरीदारी घटाई, ऐसी खबरें सुर्खियों में रही हैं। अब अगर ये पहलू ट्रेड डील का हिस्सा है, तो यह बेहद आपत्तिजनक बात होगी। इसलिए कि यह अपने संप्रभु निर्णय को किसी अन्य देश की भू–राजनीतिक जरूरतों के सामने समर्पित करने जैसा होगा। दरअसल, खरीदारियों के बारे में भी कोई व्यक्ति या देश अपनी जरूरत एवं बाजार के तर्कों से फैसला लेता है। किसी दबाव में आकर इस बारे में बंधना अपने हितों से समझौता होगा। अमेरिका में टैरिफ 18 प्रतिशत होने से वस्त्र, जेवरात आदि जैसे श्रम–केंद्रित उद्योगों को राहत अवश्य मिलेगी। लेकिन अमेरिका की भू–राजनीतिक रणनीतियों से जुड़ी शर्तें ट्रेड डील में शामिल हुईं, तो आर्थिक के साथ–साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए भी वो नुकसान का पहलू होगा।

अब कमंडल ही मंडल हो गया

हरिशंकर व्यास

यह सवाल इसलिए है क्योंकि भाजपा सरकार ने विश्व विद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से ऐसा नया नियम जारी कराया, जिससे देश के करीब ढाई हजार उच्च शिक्षा संस्थानों की तस्वीर बदल जाती। यह कहना अतिरंजित लग सकता है लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर यूजीसी के नियम उसी रूप में लागू होते, जिस रूप में उनको जारी किया गया था तो देश के उच्च शिक्षण संस्थान नब्बे के दशक का बिहार और उत्तर प्रदेश बन सकते थे। लालू यादव की पार्टी की एक प्रवक्ता ने इसका इशारा भी किया था। जब इन नियमों के हवाले उससे पूछा गया कि इसके जरिए तो अगड़ी जाति के छात्रों और शिक्षकों को फंसाया जा सकता है तो उसने दो टूक अंदाज में कहा कि इनको फंसाया जाना चाहिए क्योंकि ये 90 फीसदी बहुजन के अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उसने हजारों साल के दमन, अत्याचार वगैरह की बातें भी कहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब यूजीसी के नियमों पर रोक लगाई तो सुनवाई के दौरान लालू यादव की पार्टी की प्रवक्ता के उस बयान का भी जिक्र एक वकील ने किया था। पहले कानून के हिसाब से देखें तो भारत में माना जाता है कि हर अच्छे कानून का दुरुपयोग हो सकता है। लोग उसमें लूप होल्स निकाल ही लेते हैं। लेकिन जब कानून ही खराब हो तो क्या होगा? तब तो उस कानून के दुरुपयोग की जरुरत नहीं है। फिर तो उसके सदुपयोग से भी लोगों को फंसाया जा सकता है या किसी को बचाया जा सकता है। यूजीसी ने जो नए नियम जारी किए थे वो नियम इस दूसरी श्रेणी में आते हैं। वे इतने खराब हैं कि उनके दुरुपयोग की जरुरत नहीं है। उनके सदुपयोग से भी देश के एक छोटे से जातीय समूह के छात्रों और शिक्षकों को फंसाया जा सकता है और उनके करियर पर ग्रहण लगाया जा सकता है। ध्यान रहे शिक्षण संस्थानों में किसी तरह का भेदभाव रोकने के नियम पहले से बने थे। यूपीए सरकार के समय यूजीसी ने 2012 में नियम बनाए थे, जिनमें सभी छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के प्रावधान किए गए थे। लेकिन 2026 में नरेंद्र मोदी की सरकार के समय जो नियम जारी किए गए उसमें कई चीजें बदल दी गईं। पहले नियम में सिर्फ भेदभाव की बात कही गई थी, जबकि नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की बात जोड़ दी गई और सामान्य वर्ग को छोड़ कर बाकी सबको भेदभाव के संभावित शिकार के तौर पर परिभाषित किया गया। इसी तरह पुराने नियम में गलत शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान था, जिसे नए नियमों में हटा दिया गया। इस तरह गलत शिकायत करके किसी को फंसाने का लाइसेंस दिया गया। पुराने नियम में शिकायत सुनने वाली कमेटी में सभी वर्गों के सदस्य रखने का प्रावधान था, जबकि नए नियम में एससी, एसटी, ओबीसी सदस्य रखने को अनिवार्य किया गया और सामान्य वर्ग का सदस्य रखने की अनिवार्यता नहीं रखी गई। नए नियम में भी रैगिंग को शामिल नहीं किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर रैगिंग का शिकार सामान्य वर्ग का कोई लड़का शिकायत करे तो क्या उसके ऊपर भी भेदभाव की कार्रवाई हो सकती है। सवाल है कि क्या यूजीसी ने बिना सोचे समझे ये नियम जारी कर दिए या कोई ऐसा बैठा है, जिसके मन में सामान्य वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह है और उसने सबक सिखाने के लिए इस तरह के नियम बनाए या सोच समझ कर राजनीतिक योजना के तौर पर ये नियम बनाए गए ताकि राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं के हाथ से बहुजन राजनीति का कार्ड छीना जा सके? ध्यान रहे लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से नरेंद्र मोदी और उनकी टीम बहुत सावधान हो गई है। उससे पहले भाजपा अपने को अजेय मान रही थी और लग रहा था कि कांग्रेस या उसके नेतृत्व में एकजुट विपक्ष भी कभी उसको नहीं हरा पाएगा। लेकिन संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ, जाति गणना कराओ आदि के नारे पर विपक्ष ने भाजपा की हवा निकाल दिया। लोकसभा चुनाव में चार सौ सीट हासिल करने के लक्ष्य को पंक्चर किया। शजितनी आबादी उतना हक्य का राहुल गांधी का नारा हिट हुआ। तभी पिछड़ा, दलित और आदिवासी की ओर ध्यान गया। पहले नरेंद्र मोदी जिस तरह शमुफ्त की रेवड़ीच से घबराए उसी तरह जाति वाले दांव से घबराए हुए हैं। ध्यान रहे नरेंद्र मोदी ने ही शमुफ्त की रेवड़ीच का जुमला बोला था। उन्होंने कहा था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाएगी। लेकिन जब लगा कि शमुफ्त की रेवड़ीच का दांव विपक्ष के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस कर्नाटक जीत गई और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं हार रहे हैं। तो उन्होंने भी सबको खजाना खोलने की इजाजत दी। मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना को देश भर में भाजपा ने भी आजमाया। उसी तरह बिहार में जाति गणना हुई और राहुल ने कर्नाटक, तेलंगाना में इसकी घोषणा की तो प्रधानमंत्री ने भी आगे बढ़ कर जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। अगले साल जनगणना होगी, जिसमें 1931 के बाद पहली बार देश भर की जातियों की गिनती होगी।

ओरण के अस्तित्व के लिए राष्ट्रीय गौसेवा नीति

कौशल

आयुर्वेद में गाय के दूध से बने देसी घी की तुलना अमृत से की गई है। स्वास्थ्य के लिए इसे हानिकारक बताने की राजनीति भी इस कड़ी में शामिल है। इसके पीछे यदि कोई ठोस आधार रहा होता तो अब तक सामने अवश्य आता। यह अमेरिकी शफार्मा लॉबीश और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बीच गठजोड़ को ही दर्शाता है। इस मामले में एक ऐसी शराष्ट्रीय गोसेवा नीतिश की जरूरत है राजस्थान के करीब 41 लाख एकड़ शओरण भूमिश पर संकट के बादल छाए हुए हैं। सूबे की सरकार ने जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर और पाली जिले में शसोलर पार्कश जैसे व्यावसायिक कार्यों के लिए नियमों को ताक पर रखकर सैंकड़ों एकड़ ऐसी जमीन का भू–उपयोग बदलकर जनता को विरोध के लिए मजबूर किया है। इस शओरण क्षेत्रश को देश के अन्य क्षेत्रों में शदेवभूमि,श शदेवबनीश और शगोचरश कहा जाता है।सार्वजनिक उपयोग के कारण इसका नियंत्रण ग्रामसभा के आधीन होता है इसलिए ग्राम पंचायत की सहमति के बिना सरकार इस परिवर्तन के लिए अधिकृत भी नहीं है। ऐसा करने से पहले उतनी ही भूमि गोचर–ओरण के लिए अन्यत्र आवंटित करने का विधान है। इसके विरुद्ध ग्रामसभा प्रस्ताव पारित कर प्रशासन को ज्ञापन देने के साथ धरना–प्रदर्शन व यात्रा निकालकर जन–जागरण और सत्याग्रह करने में लगी है। सरकार और प्रशासन की कोशिशों के बावजूद यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी के साथ शअरावली संरक्षण आंदोलनश भी सुर्खियों में है।उच्चतम न्यायालय केन्द्र सरकार की अनुशंसा पर 20 नवम्बर, 2025 को अरावली पर्वत की परिभाषा बदल देता है। राजस्थान और गुजरात ही नहीं, बल्कि दिल्ली और हरियाणा में भी जनता इसका विरोध करने लगी है। लगातार बढ़ते इस विरोध को ध्यान में रखकर 27 दिसम्बर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने इस पर स्थगनादेश जारी कर सुनवाई शुरू की, लेकिन सरकार और न्यायालय की मंशा भांपकर आम लोग सार्वजनिक उपयोग की जमीन को बचाने के लिए संघर्ष का बिगुल फूंक चुके हैं। शअरावली संरक्षण आंदोलनश और शओरण क्षेत्रश की रक्षा में लगे समूह एकजुट हो रहे हैं। जन–जागरण के लिए दोनों समूहों की सक्रियता साफ दिखती है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि उद्योगपतियों को सौंपने के मामले में सरकार को आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना होगा।गौरक्षा आंदोलन के प्रवर्तक संत समाज के लोग भी इस जनांदोलन से जुड़कर विरोध दर्ज कर रहे हैं। हालांकि राजसत्ता के सामने इनकी हस्ती भी 1966 से ही शपब्लिक डोमेनश में रही है। इंदिरा गांधी की सरकार ने देश को आईना दिखाया था। महात्मा गांधी और संघ परिवार से जुड़े धर्मपाल जी की अध्यक्षता में शराष्ट्रीय पशु आयोगश का गठन कर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक पहल अवश्य शुरू की थी। सत्तारूढ़ भाजपा के एजेंडे में अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना की तरह यह एक अहम मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सरकारी आवास में गोसेवा का कार्य यही संकेत करता है। गोसेवा से जुड़े इस मामले की सभी कड़ियों को ध्यान में रखकर सरकार और समाज को देशहित सुनिश्चित करना चाहिए।उन्नीसवीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति इतनी खराब थी कि इसे ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा होना पड़ा था। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर गौहत्या का नया दौर शुरू हुआ। हालांकि गोकशी मुगलों के समय ही जारी

थी। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर कत्लखाने बनाए थे। अंग्रेजी राज में सन् 1808 से 1947 के बीच बाजार को ध्यान में रखकर खोले गए बूचड़खाने की वजह से गाय का मांस और खाल विदेशी बाजार की जरूरतों को भी पूरा करने लगा। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान के अनुच्छेद 48 में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने का असफल प्रयास अवश्य शुरु हुआ, लेकिन शोषण की यह दास्तान आज भी जारी है। इस नई औपनिवेशिक परंपरा को तोड़ना भारतीय अस्मिता से जुड़ा गंभीर मामला है। गांधी इसे स्वतंत्रता की प्राप्ति से रत्ती भर कमतर नहीं आंकते थे। राजस्थान की स्थानीय संस्कृतियों से इतर पश्चिमी देशों के राजनीतिक दर्शन में वैज्ञानिक तकनीकी की अहम भूमिका है। इसका प्रभाव युद्ध से लेकर प्रकृति के दोहन तक विद्यमान है। इसने शारीरिक श्रम पर आधारित कृषि व गौसेवा के भारतीय दर्शन को बदलकर रख दिया है। गोबर और गोमूत्र जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों की वजह से क्षय हुई भूमि की गुणवत्ता सुधारने में इनकी अहम भूमिका हो सकती है। इक्कीसवीं सदी में शश्री–अन्नश की पैरवी करने वाला भारत क्या अपनी ही पुरानी कृषि संस्कृति का पुनरुद्धार कर सकेगा? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के क्रम में कई गांठों को खोलने की आवश्यकता है। आजादी के बाद खेत जोतने में सक्षम बैलों की जगह ट्रेक्टर का इस्तेमाल प्रचलन में आ गया है। कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक से दूसरा हमला भी किया गया। बैल और नंदी की जरूरत खत्म होती गई। शगोचर भूमिश पर इन पशुओं के लिए चारागाह का प्रबंध था। इसे समाप्त कर कृत्रिम चारा का भी इस्तेमाल होने लगा। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर ही गोवंश और शगोचर भूमिश को बचाने की मुहिम सफल हो सकती है। इस मामले में एक और बात नजरंदाज करने योग्य नहीं है। आयुर्वेद में गाय के दूध से बने देसी घी की तुलना अमृत से की गई है। स्वास्थ्य के लिए इसे हानिकारक बताने की राजनीति भी इस कड़ी में शामिल है। इसके पीछे यदि कोई ठोस आधार रहा होता तो अब तक सामने अवश्य आता। यह अमेरिकी शफार्मा लॉबीश और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बीच गठजोड़ को ही दर्शाता है। इस मामले में एक ऐसी शराष्ट्रीय गोसेवा नीतिश की जरूरत है, जो गौ–हत्या रोकने और शगोचर भूमिश संरक्षण के साथ ही इन सभी समस्याओं को दूर करती हो। कृतज्ञता और सभी का हित गाय के प्रति श्रद्धा का मूल आधार है। शराष्ट्रीय गोसेवा नीतिश के केन्द्र में इन्हें होना चाहिए।

संविधान की छाती पर पाइंट ब्लैंक फायर

राजेन्द्र

संघ–भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, खासतौर पर मोदी–शाह जोड़ी की, ऐसे सभी मामलों में चुप्पी वैसे तो एक आम कायदा ही है, फिर भी आने वाले विधानसभाई चुनावों के संदर्भ में यह चुप्पी उनके लिए और भी जरूरी है। यह थोड़े भी राजनीतिक रूप से सजग, तटस्थ प्रेक्षकों से छुपा नहीं हैं कि आम तौर पर आने वाले राज्य विधानसभाई चुनावों में और खासतौर पर असम और प. बंगाल में विधानसभा के चुनावों में, संघ परिवार को अपनी अति–उपयोग से बुरी तरह घिस चुकी, हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक तुरुप का ही सहारा है।आखिरकार, हिमांत बिश्वशर्मा ने और अकेले विश्व शर्मा ने ही नहीं, उनके नेतृत्व में भाजपा की असम इकाई ने भी, भारतीय संविधान को खुली चुनौती दे ही दी। भाजपा के आधिकारिक हैंडल से प्रसारित एक वीडियो संदेश में, बिश्वशर्मा हाथों में तरह–तरह की बंदूकें पिस्तौलें लिए, अमरीकी फिल्मों के कॉउबाय की मुद्राओं में प्रकट ही नहीं हुए, वह अपने हथियारों से गोलियां दागते हुए दिखाई भी दिए। याद रहे कि बंदूकों के साथ अपने गीतों को फिल्माने के लिए ही पंजाब में तथा अन्यत्र कई गायकों को हिंसा को बढ़ावा देने की धाराओं में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। इस गन कल्चर को एक गंभीर खतरे की तरह चित्रित किया जाता रहा है। लेकिन, भाजपायी मुख्यमंत्री हिंसा के जरिए अपनी मर्दानगी के प्रदर्शन तक ही नहीं रुके।इससे आगे बिश्वशर्मा ने, फासीवादी नरसंहार का मॉडल पेश करने के रास्ते पर लंबी छलांग लगायी। बिश्वशर्मा ने सीधे जिंदा लोगों पर निशाना लगाया। और निशाने का चुनाव उनकी मर्दानगी के वास्तविक चरित्र का पूरी तरह से खुलासा कर देने वाला था। निशाने पर जो दो लोग नजर आते हैं, वेशभूषा से साफ तौर पर मुसलमान हैं–एक अपेक्षाकृत युवा और एक अधेड़। शर्मा निशाना साधकर गोली दागते नजर आते हैं। और भाजपायी वीडियो खुशी से एलान करता है–पाइंट ब्लैंक! किसी टिप्पणीकार ने ध्यान दिलाया कि पाइंट ब्लैंक के फायर से संघ परिवार का नाता पुराना है। जनवरी 1948 में जब गोडसे की पिस्तौल से निकली तीन गोलियों ने महात्मा गांधी की जान ली थी, वह फायर भी पाइंट ब्लैंक का बताया गया था।स्वाभाविक रूप से, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार के इस तरह के खुले आह्वान पर, मुख्यधारा के मीडिया पर संघ–भाजपा के पूर्ण नियंत्रण के बावजूद, काफी हो–हल्ला मचा। अन्य चीजों के अलावा इस पर भी तीखी टिप्पणियां आयीं कि शर्मा के नेतृत्व में असम भाजपा द्वारा उक्त वीडियो विज्ञापन ठीक उस समय जारी किया गया था, जब उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी 65 फीसद से अधिक मुस्लिम आबादी वाले और घोषित रूप से इस्लामी राज्य, मलेशिया की मेहमान नवाजी का आनंद ले रहे थे, जिसमें रामकथा की कठपुतली प्रस्तुति समेत, हिंदू परंपराओं के अनेक तत्वों से लेकर, तमिल भाषा व संस्कृति के अनेक तत्वों के साथ मलेशियाई जनता के जिंदा रिश्तों के प्रदर्शन भी शामिल थे। परदेश में मोदी मुस्लिम नेताओं को गले लगा रहे थे और भारत में उनकी डबल इंजन सरकार का असम का डिब्बा, मुसलमान की पहचान कर, पाइंट ब्लैंक से फायर कर रहा था!निंदा के इन स्वरों को अपने अनुमान से ज्यादा तेज होता देखकर, असम भाजपा ने अपने हैंडल से उक्त विज्ञापन वीडियो को डिलीट कर दिया। लेकिन, यह तभी किया गया, जब पहले यह सुनिश्चित कर लिया गया कि लाखों संघ–भाजपा समर्थक, इस वीडियो को देख चुके थे और आगे शेयर करने की शृंखलाएं शुरू कर चुके थे। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि संघ–भाजपा ने खंडन–मंडन के इस तरह के धतकर्म में खूब महारत हासिल कर रखी है। किसी उकसावेपूर्ण सांप्रदायिक और इसलिए संविधान पर चोट करने वाले संदेश को हवा में उछाल कर, इसकी थाह लेना कि संविधान की रक्षा करने वाली ताकतों में इस पर कैसी तथा कितनी प्रतिक्रिया होती है और फिर यह सुनिश्चित करने के बाद कि उक्त संदेश उसकी कतारों तक फैल जाए, रस्मी तौर पर उस संदेश को वापस ले लेना या उसका खंडन कर देना, उनका जाना–पहचाना खेल है। और इस खेल के बाद हर बार, सांप्रदायिक संदेश की नग्नता की सीमा को आगे बढ़ाया जा रहा होता है। इस खेल में बिश्वशर्मा के नेतृत्व में असम भाजपा, सत्ताधारी पार्टी की अन्य राज्य इकाइयों से भी सवायी दुस्साहसी ही होगी, किसी से कम नहीं। हैरानी की बात नहीं है कि भाजपा की असम इकाई के लिए अपने संदेशों में अल्पसंख्यकों के नरसंहार के इशारे करना भी कोई नयी बात नहीं है। अभी कुछ ही महीने पहले, दो अलग–अलग संदर्भों में और दूसरी बार तो संभवतरू बिहार के विधानसभाई चुनाव में भाजपा–जदयू गठजोड़ की जीत के बाद, भागलपुर के अस्सी के दशक के भयावह दंगों में एक हड्डिड्डयों को जमा देने वाली घटना में, लोगाईं गांव में दर्जनों मुसलमानों की हत्या के बाद, खेतों में लाशें गाढ़कर, उन पर गोभी बो देने के प्रसंग की, संस्तुतिपरक तरीके से याद दिलायी गयी थी। उस नातिपरोक्ष इशारे से, पाइंट ब्लैंक तक की यात्रा, पूरी तरह से अप्रत्याशित तो नहीं ही थी। हैरानी की बात नहीं है कि इस मामले पर सारे शोर–शराबे के बावजूद, संघ–भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी तक शामिल हैं, नरसंहार के उक्त जघन्य संदेश से किसी भी तरह से दूरी बनाना तक जरूरी नहीं समझा है। वास्तव में उन्हें तो इसका नोटिस तक लेने की तकलीफ करना भी गवारा नहीं हुआ है। पूरे संघ–भाजपा प्रतिष्ठड्डान की ओर जाहिर है कि उसके द्वारा नियंत्रित मुख्यधारा के मीडिया की भी मुद्रा, मूंदेहु आंख कहूं कछु नाहीं की ही बनी रही है। उनके लिए तिनके की ओट के तौर पर इतना भर काफी है कि आपत्तिजनक बताया जा रहा वीडियो संदेश तो सार्वजनिक पटल पर है ही नहीं–उसे तो पहले ही हटाया जा चुका है! जिसे हटाया जा चुका है, उस पर विवाद कैसा? संघ–भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, खासतौर पर मोदी–शाह जोड़ी की, ऐसे सभी मामलों में चुप्पी वैसे तो एक आम कायदा ही है, फिर भी आने वाले विधानसभाई चुनावों के संदर्भ में यह चुप्पी उनके लिए और भी जरूरी है। यह थोड़े भी राजनीतिक रूप से सजग, तटस्थ प्रेक्षकों से छुपा नहीं हैं कि आम तौर पर आने वाले राज्य विधानसभाई चुनावों में और खासतौर पर असम और प. बंगाल में विधानसभा के चुनावों में, संघ परिवार को अपनी अति–उपयोग से बुरी तरह घिस चुकी, हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक तुरुप का ही सहारा है। वास्तव में खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक तुरुप का केंद्रीय आधार के रूप में सहारा लेने की शुरूआत तो, 2024 के आम चुनाव के दूसरे–तीसरे चरण से ही शुरू हो गयी थी, जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका खतरा दिखाना शुरू कर दिया था कि अगर सत्ता उनके विरोधियों के हाथ में आ गयी तो वे हिंदुओं से छीनकर उनकी भेंस, जमीन, मंगलसूत्र, आरक्षण और न जाने क्या–क्या, मुलसमानों को दे देंगे, जिनका तुष्टड्डीकरण ही उनका मुख्य काम है!उसके बाद से पहले झारखंड में, उसके बाद बिहार में, विधानसभा चुनाव के हरेक चर्क्र में मोदी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में, हिंदुओं के लिए शछीन लेंगे, मुसलमानों को बांट देंगेश के खतरे के इस राग का स्वर तेज से तेज ही किया गया है। हैरानी की बात नहीं है कि विधानसभा चुनाव के इस चक्र में, जो उस समय आ रहा है जब मोदी के नेतृत्व में डबल इंजनिया राज के पास, अपनी चौतरफा विफलताओं के सामने, जनता को बहलाने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है, खतरे के इस जाप को और भी तेज किया जाने वाला है। इसके पर्याप्त संकेत मोदी और शाह ने अब तक तथाकथित घुसपैठियों के खतरे के अपने बखानों और उन्हें चुन–चुनकर निकालनेश के ऐलानों से दे भी दिए हैं।

त्वरित विकास को समर्पित कल्याणकारी केन्द्रीय बजट

डॉ. महेन्द्र सिंह

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2026–27 के लिए संसद में पेश किया गया गया बजट देश के त्वरित विकास को समर्पित कल्याणकारी बजट है। इस बजट में समाहित प्रस्तावों में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने और उसे निरन्तर बनाये रखने पर जोर दिया गया है। साथ ही, लोककल्याण के लिए बजट प्रस्तावों पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में तीन कर्तव्यों को उजागर किया। ये हैं रू () अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के प्रति लचीलेपन में वृद्धि करते हुए आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे बनाये रखनाय जन आकाँक्षाओं की पूर्ति और उनकी क्षमताओं का वर्द्धन करना एवं देश के प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और वर्ग तक संसाधनों, सुविधाओं तथा अवसरों की पहुंच को सुनिश्चित करना। इस तरह ये कर्तव्य मोदी सरकार की सर्वसमावेशी एवं पोषणीय विकास की रणनीति को सुस्पष्ट रूप में परिभाषित करते हैं। ध्यातव्य है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के केन्द्र में एक ओर आर्थिक संवृद्धि की गति को तेज करना रहा है वहीं दूसरी तरफ सापेक्षतया वंचित लोगों एवं क्षेत्रों को उनकी क्षमता व सामर्थ्य को बढ़ाते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करना रहा है। इस दृष्टि से यह कहना समीचीन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास का ध्येय वाक्य लोकनीतियों के प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन का नाभिकेन्द्र रहा है। इसमें आर्थिक समृद्धि एवं लोककल्याण में वृद्धि स्वतरू विहित रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा संरचनात्मक आर्थिक सुधारों का मूल विचार रिफार्म, परफार्म व ट्रॉन्सफार्म रहा है। इस बजट में भी, बजट प्रावधानों को अधिक परिणामोन्मुखी बनाने के लिए सुधारों के क्रम को जारी रखा गया है। विकसित भारत के महालक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस बजट में कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र, एमएसएमई, ओडीओपी, रिन्यूबल व न्यूक्लियर एनर्जी, सेमिकंडक्टर, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, जलमार्ग व रेल विकास, डिकार्बनाइजेशन, निर्यात संवर्द्धन, रक्षा क्षेत्र इत्यादि संभावनापूर्ण क्षेत्रों एवं तत्सम्बन्धी क्रियाओं के संवर्द्धन व विकास के लिए वित्तमंत्री द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित आवंटन किए गये हैं। साथ ही, मानव पूँजी के निर्माण से सम्बन्धित क्षेत्रों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, युवा और दिव्यांग सशक्तिकरण पर पर्याप्त बल दिया गया है। वस्तुतरू, मानव पूँजी के बेहतर विकास से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा जनकल्याण में वृद्धि होगी। वित्तमंत्री ने इस बजट में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को जारी रखते हुए इस पर विशेष बल दिया है। हाल के वर्षों में जीडीपी के सापेक्ष राजकोषीय घाटा में निरन्तर गिरावट से इस बात की पुष्टि होती है कि मोदी सरकार का राजकोषीय प्रबन्धन सम्बन्धी निष्पादन श्लाधनीय रहा है। वर्ष 2021–22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.7 प्रतिशतय 2022–24 में 6.5 प्रतिशत 2023–24 में 5.5 प्रतिशतय 2024–25 में 4.8 प्रतिशत एवं 2025–26 में 4.4 प्रतिशत था। इसे 2026–27 के बजट में कम करके 4.3 प्रतिशत पर रख गया है। ये प्रवृत्तियाँ राजकोषीय व्यवस्था की मजबूती की परिचायक हैं। मोदी सरकार की राजकोषीय प्रवीणता एवं बेहतर वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि जीडीपी के सापेक्ष राजकोषीय घाटा निरन्तर घटा है। साथ ही, वित्तमंत्री इस बात में भी सफल रही हैं कि उन्होंने इस बजट में जीडीपी के सापेक्ष केन्द्र सरकार के ऋण को 55.6 प्रतिशत पर रखा है। यह वर्ष 2025–26 के लिए 56.1 प्रतिशत रखा गया था। साथ ही, इस बजट में जीडीपी के सापेक्ष राजस्व घाटा एवं प्राथमिक घाटा में भी कमी आई है। घटते घाटे एवं ऋण से निजी पूँजी निवेश में वृद्धि होगी। इस बजट में, राजस्व में सतत वृद्धिय पूँजीगत व्यय में वृद्धि और राजकोषीय पारदर्शिता में सुधार के संकेतकों से भी देश की राजकोषीय सुदृढ़ता की पुष्टि होती है। पूँजीगत खर्च के जरिये अवस्थापना क्षेत्र के विकास ने विकास को तेज करने और रोजगार को बढ़ाने में उल्लेखनीय तौर पर योगदान दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक विकास में धमनियों का कार्य करता है। इसलिए यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर मोदी सरकार द्वारा किया गया निवेश लगातार विकास का इंजन बना हुआ है। एक ओर जहाँ केन्द्र सरकार स्वयं पूंजीगत व्यय को बढ़ा रही हैय वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारों को भी अनुदान व ऋण देकर उनके पूँजीगत खर्च को बढ़ाने में मदद कर रही है। वर्ष 2025–26 की तुलना में 2026–27 के बजट में पूँजीगत आवंटन में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि को भी जोड़ लिया जाय तब प्रभावी पूँजीगत व्यय की वृद्धि 22 प्रतिशत बैठती है। इस तरह मोदी सरकार की यह विचारणा सुस्पष्ट होती है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती आर्थिक उन्नति का मूलाधार है। इस बजट में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों क्षेत्रों में पूँजीगत व्यय की वृद्धि दरें इस तरह हैंरू टेलीकॉम 97 प्रतिशतय रक्षा 18 प्रतिशतय रेलवे 10 प्रतिशतय सड़क व हाईवे 8 प्रतिशत एवं आवास व नगरीय विकास 6 प्रतिशत। यह तथ्य यह भी दर्शाते हैं कि बेहतर राजकोषीय प्रबन्धन से अब विकासगामी क्रियाओं के लिए अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। जीडीपी के सापेक्ष सरकारी ऋण भार को घटाकर 2030–31 तक 50 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। स्पष्ट है कि इससे आगामी वर्षों में अवस्थापना के विकास के लिए और अधिक फिस्कल स्पेस मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि पूँजीगत व्यय में मोदी सरकार द्वारा की गई वृद्धि से आय में तो कई गुना वृद्धि होती ही है, इससे रोजगार में भी उल्लेखनीय तौर पर वृद्धि होती है। इस बजट में छोटे, मझोले एवं धार्मिक नगरों के विकास के लिए भी प्रावधान किए गये हैं। नगरीय क्षेत्रों में जन सुविधाओं के बेहतर विकास से जनजीवन सुगम व स्वस्थ होगा। साथ ही, इसके विकास से कारोबार सुगम होगा, इसमें वृद्धि होगी। धार्मिक व साँस्कृतिक स्थलों के उन्नयन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा देश–विदेश से पर्यटकों की आवाजाही से आर्थिकी सशक्त होगी। इस बजट में हास्पिटेलिटी तथा हेल्थ टूरिज्म से भी लोगों की आजीविका के स्रोतों में वृद्धि, रेल एवं जलमार्गों के विकास एवं अपग्रेडेशन से लाजिस्टिक्स की लागतें घटेंगी। इससे व्यापार में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी और अर्थव्यवस्था की स्पर्धात्मकता में वृद्धि से निर्यात–प्रेरित निवेश होगा। इस बात का उल्लेख करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस बजट में अवस्थापना क्षेत्र के विकास के लिए 12.20 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। यह एक बड़ी धनराशि है। इससे विकास की गति को तेज करने तथा रोजगार को बढ़ाने में महती सहायता मिलेगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के अन्तर्गत इस बजट में 40 हजार करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त जिन 7 रोजगारपरक क्षेत्रों को समावेशित किया गया है वे हैंरू बायो फार्मा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रानिक्स कंपोनेन्टस, रेयर अर्थ, रसायन, पूँजीगत वस्तएँ और टेक्सटाइल्स। इनसे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की संवृद्धि बढ़ेगी। वस्तुतरू, ये अर्थव्यवस्था के उदीयमान क्षेत्र हैं और इनमें उत्पादन, रोजगार व निर्यात की प्रचुर संभावनाएं हैं।

सहारा शहर बनेगा सत्ता का नया केंद्र, यहां विधानसभा भवन बनाने की कवायद तेज

लखनऊ, (संवाददाता)। एलडीए के अधिकारी ने बताया कि करीब 10 महीने पहले एलडीए ने सहारा शहर में अपने हिस्से की 75 एकड़ जमीन कब्जे में ली थी। इसके बाद सितंबर में नगर निगम ने अपने हिस्से की 170 एकड़ जमीन को लीज निरस्त करने के बाद कब्जे में लिया था। इस तरह कुल 245 एकड़ जमीन खाली हो गई है। अब इसी जमीन पर नया विधानभवन बनाने की तैयारी है। शासन के निर्देश पर जमीन की पैमाइश रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। उच्च स्तर पर यहां विधानभवन निर्माण के लिए सहमति बन चुकी है। आगे की प्रक्रिया के लिए ही कंसल्टेंट नियुक्त करने और उसके जरिये डीपीआर और डिजाइन तैयार करने की तैयारी है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि कि सहारा शहर की जमीन पर विधानभवन निर्माण के संबंध में प्रक्रिया चल रही है। जानकारों का कहना है कि सरकार नया विधानभवन बनाने के लिए करीब 200 एकड़ जमीन की तलाश कई वर्ष से कर रही थी। यहां नगर निगम की 170 और एलडीए की 75 एकड़ जमीन मिलाकर कुल जमीन 245 एकड़ है। यह जगह लोकेशन व आवागमन के हिसाब से भी उपयुक्त भी है। इसी वजह से शासन ने इसी जगह पर नया विधानभवन बनाने का मन बनाया है। नए विधानभवन से होंगी ये सहूलियतें लोकभवन और विधानभवन में मुख्यमंत्री के आने और वहां से लौटने के समय कई जगह ट्रैफिक रोका जाता है। इससे लोगों को सहूलियत मिल जाएगी। वर्तमान विधानभवन के आसपास पार्किंग की बड़ी समस्या है। बड़ी संख्या में गाड़ियां सड़क पर खड़ी होती हैं। इससे राहत मिल सकती है हजरतगंज और लालबाग में बड़े अस्पताल और स्कूल भी हैं ऐसे में वीआईपी मूवमेंट के समय ट्रैफिक बंद किए जाने से लोगों को परेशानी होती है जो दूर होगी। नए विधानभवन के बनने के बाद हजरतगंज को बेहतर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना आसान होगा। अभी सुरक्षा कारणों और यातायात दबाव के कारण कई योजनाएं नहीं बन पा रहीं।

डीएम ने किया कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण मिली खामिया

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने शासन के निर्देश के क्रम कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न कार्यालयों एवं पटलों का जिसमे जिलाधिकारी नगर, प्रशासन, वित्त एवं राजस्व, नजारत, निबंधन, आपदा प्रबन्धन आदि का स्थलीय निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर में स्थित आवासीयध्अनवासीय भवनों में साफ सफाई की स्थिति, जन सामान्य के लिए बैठने, पेयजल, शौचालय, वाहन पार्किंग, भवन मरम्मत, साफ–सफाई आदि की समुचित व्यवस्था का जायजा लिया।उन्होंने अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में निर्देश दिया कि अभिलेखों को क्रमानुसार रखा जाए और फाइलों को सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही फर्नीचर यदि खराब पाये गये हैं।उन्हें दुरुस्त कराने अथवा नए फर्नीचर की व्यवस्था कराएं जाने के निर्देश दिए। जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने परिसर में कई स्थानों पर विद्युत तारों को सुनियोजित करने तथा खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ठीक कराने के निर्देश संबंधित को दिए। शौचायलयों का निरीक्षण करते समय उन्होंने निर्देश दिया कि नियमित रूप से प्रत्येक दिवस में दो बार शौचालयो की साफ सफाई कराई जाए।महिला और दिव्यांग शौचायलयों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वह सुनिश्चित कराई जाए।साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही कूड़ा–करकट रखने के लिए उचित स्थान पर डस्टबिन रखी जाए। लोगो के बैठने की व्यवस्था ठीक रखी जाए।स्वच्छ पेयजल सभी कार्यालय में सुनिश्चित कराया जाए।निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी नगर, अपर जिलाधिकारी वि0ध्रा0 सहित संबंधित विभागाध्यक्ष उपस्थित रहें।

संक्षिप्त खबरें

बड़े बकायेदारों पर नगर निगम का चला चाबुक,लगभग 11 लाख रुपये वसूले

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।नगर निगम ने गृहकर एवं जलकर की वसूली के लिए अभियान को और तेज कर दिया है। बुधवार को 14 बड़े बकाएदारों के यहां छापामारी कर 11 लख रुपये की वसूली की गई।अपर आयुक्त सुमित कुमार ने बताया कि वसूली के लिए गठित दल में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेंद्र कुमार, कर निर्धारण अधिकारी विनय प्रताप सिंह, कर अधीक्षक जयप्रकाश तथा अन्य कर्मी शामिल थे।टीम ने कौशल शपुरी स्थित अवध होटल से एक लाख रुपये, त्रिपाठी होटल से सहादतगंज से दो लाख रुपये, आजाद प्रकाशन से 3.28 लाख रुपये, मेगा शाप से एक लाख, ट्रिपल लाइन होटल से 1.26 लाख रुपये, जयप्रकाश नारायण वार्ड के गोपाल रस्तोगी से एक लाख रुपये, भूपेंद्र कुमार से 67047 रुपये, सेठ लड्डू लाल से 62700 रुपये की वसूली कर मौके पर ही रसीद सौंपी गई। इसमें गोपाल रस्तोगी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो रोक दी गई। उन्होंने बताया कि एमएस फर्नीचर, मंत्रा होटल, पुष्पक इन होटल सहित कई बड़े बकायेदारों को एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने की चेतावनी दी गई है।

चौरासी कोसी,चौदहकोसी, आवास विकास एवं रिंग रोड परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण की प्रगति की डीएम ने किया समीक्षा

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।जनपद में संचालित चौरासीकोसी, चौदहकोसी, आवास विकास परिषद एवं रिंग रोड परियोजनाओं के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण एवं प्रतिकर भुगतान की प्रगति के संबंध में एक आवश्यक समीक्षा बैठक डीएम निखिल टीकाराम फुंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।बैठक में रिंग रोड एवं आवास विकास परिषद से संबंधित अवशेष ग्रामों के अभिनिर्णय किए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। साथ ही अभिनिर्णित ग्रामों में प्रभावित काश्तकारों को अवशेष धनराशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए।जिलाधिकारी ने कहा कि जिन स्थानों पर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो।बैठक में अपर जिलाधिकारी (भू .अ.) कौशल कुमार, अपर जिलाधिकारी (विध्रा) अमित भट्ट सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश में और महंगा होगा बीएड करना, आवेदन के साथ बढ़ाया जाएगा ऑनलाइन काउंसिलिंग का पंजीकरण शुल्क

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाले आवेदन का शुल्क उच्च शिक्षा विभाग ने बढ़ा दिया है। प्रवेश आवेदन शुल्क जहां 250 रुपये बढ़ाया गया है। वहीं ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण शुल्क में भी सौ रुपये की वृद्धि की गई है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार देर रात से शुरू हो गए हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन पिछले तीन साल से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी की ओर से किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर उच्च शिक्षा विभाग ने बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुल्क को संशोधित करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार सामान्य, ओबीसी व प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1400 से बढ़ाकर अब 1650 रुपये कर दिया गया है। वहीं प्रदेश के एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 700 से बढ़ाकर 850 रुपये किया गया है। इस तरह सामान्य व ओबीसी के लिए 250 और एससी–एसटी के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये बढ़ गया है। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी की ओर से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव को भेजे पत्र में कहा गया है कि ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण शुल्क भी 850 रुपये किया गया है। जो पहले 750 रुपये था। उन्होंने कहा है कि राज्य विश्वविद्यालय (संबद्ध, सहयुक्त व घटक महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिए शिक्षण पाठ्यक्रमों प्रवेश का विनियमन) 10वें संशोधन के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित हुए अयोध्या के दंत चिकित्सक डॉ. एस.एच मेहदी

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।जनपद के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित दंत चिकित्सक डॉ. एसएच मेहदी को उनके चिकित्सा क्षेत्र में वर्षों के समर्पण, सेवा और उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।उन्हें मंगलुरु में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान अंतरराष्ट्रीय सतत दंत शिक्षा महाविद्यालय की प्रतिष्ठित अधिसदस्यता (फेलोशिप) प्रदान की गई।यह सम्मान दंत चिकित्सा के क्षेत्र में निरंतर शिक्षा, नवाचार और मरीजों के प्रति समर्पित सेवा के लिए दिया जाता है। अधिसदस्यता प्राप्त करना न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि अयोध्या जैसे ऐतिहासिक शहर के लिए भी गौरव का विषय है। इस अवसर पर देश–विदेश से आए दंत चिकित्सकों, शिक्षाविदों और चिकित्सा विशेषज्ञों की उपस्थिति में डॉ. मेंहदी को यह सम्मान सौंपा गया।डॉ. एस.एच मेहदी ने इस उपलब्धि पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके लंबे चिकित्सकीय सफर, गुरुओं के मार्गदर्शन और परिवार व सहयोगियों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि दंत चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम है, जिसके जरिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और आत्मविश्वास दिया जा सकता है। यह अधिसदस्यता उन्हें भविष्य में और अधिक उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा देगी। डॉ. मेंहदी वर्षों से अयोध्या में दंत चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और आधुनिक तकनीकों के साथ मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के लिए जाने जाते हैं। उनके इस सम्मान से न केवल चिकित्सा जगत में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, बल्कि युवा चिकित्सकों को भी निरंतर सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है।जनपद के चिकित्सकों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने डॉ. एस.एच मेहदी को इस अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

संक्षिप्त खबरें

मगहर में चार दिवसीय सम्भागीय नाट्य समारोह का शुभारम्भ

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ (संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश) एवं संत कबीर अकादमी, मगहर के संयुक्त सहयोग से सम्भागीय नाट्य समारोह 2025–26 का भव्य शुभारम्भ 9 फरवरी से संत कबीर अकादमी सभागार, मगहर में हुआ। यह चार दिवसीय नाट्य समारोह 12 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से विविध नाट्य प्रस्तुतियां मंचित की जा रही हैं। समारोह का उद्देश्य प्रदेश में रंगमंचीय गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्थानीय कलाकारों को सशक्त मंच उपलब्ध कराना और दर्शकों को गुणवत्तापूर्ण नाट्य प्रस्तुतियों से जोड़ना है।नाट्य समारोह के पहले दिन 9 फरवरी 2026 को मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक "मोटे राम का निमंत्रण" का मंचन किया गया। यह नाटक प्रेमचंद की चर्चित कथा 'निमंत्रण' पर आधारित है, जिसका नाट्य रूपांतरण एवं निर्देशन रवीन्द्र रंगधर ने किया। हास्य–व्यंग्य की पृष्ठभूमि पर आधारित इस नाटक में सामाजिक कुरीतियों और मानवीय कमजोरियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। नाटक की कथा में दिखाया गया कि किस प्रकार मोटे राम शास्त्री निमंत्रण के लालच में सात ब्राह्मणों की जगह अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर रानी साहिबा के दरबार में पहुंच जाते हैं, लेकिन मित्र चिंतामणि के पहुंचने के बाद उनका झूठ उजागर हो जाता है। नाटक अंत में एक गहरी सामाजिक सीख के साथ समाप्त होता है। हास्य और व्यंग्य से भरपूर प्रस्तुति तथा रवीन्द्र रंगधर के सधे हुए निर्देशन ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। मुख्य भूमिका में हरीश शर्मा हंस और सोना देवी ने अपने सशक्त अभिनय से पात्रों को जीवंत कर दिया और दर्शकों से खूब सराहना बटोरी।इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने के लिए सरकार पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर नए और प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे नाट्य एवं सांस्कृतिक आयोजन न केवल कलाकारों को प्रोत्साहन देते हैं, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को भी और अधिक मजबूत बनाते हैं।

कल्याणगिरी मंदिर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा

लखनऊ, (संवाददाता)। ठाकुरगंज स्थित श्री कल्याणगिरी मंदिर में रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश धारणकर भाग लिया। यात्रा जहां–जहां से गुजरी श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। नगर भ्रमण के बाद मंदिर पहुंचकर यात्रा संपन्न हुई। इसके बाद काशी से आए कथावाचक विश्वंभरनाथ शास्त्री श्डमरू जीश् महराज ने शिव महापुराण कथा शुभारंभ की। उन्होंने शिव के नाम की महिमा का बखान किया। प्रतिदिन शाम चार से रात आठ बजे तक कथा होगी। समापन पर 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर भव्य शिव बरात निकाली जाएगी। कार्यक्रम के समन्वयक एडवोकेट अनुराग पांडेय, मनीष श्रीवास्तव, अर्पित शुक्ला, दीपका त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी, उमा अवस्थी, आशा तिवारी और शर्मिला पांडेय आदि मौजूद रहे।

घरों में फल, फूल और सब्जियों के पौधे लगाएं : राज्यपाल

लखनऊ, (संवाददाता)। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जन भवन प्रांगण में आयोजित 57वीं प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी–2026 के समापन अवसर पर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। चार दिवसीय प्रदर्शनी में 1690 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 7771 प्रविष्टियां प्रस्तुत की गईं। इनमें से 1719 विजेताओं का चयन किया गया। चार दिन के दौरान 3.5 लाख से अधिक लोग पहुंचे। किसानों और उत्पादकों को लगभग 40 लाख रुपये से अधिक की बिक्री का लाभ हुआ। राज्यपाल ने सभी से अपने घरों में फल, फूल और सब्जियों के पौधे लगाने की अपील की। घर की छत पर भी फूल और सब्जियां उगाई जा सकती हैं। चिकित्सा शिविर में लगभग 1400 लोगों ने पंजीकरण कराया। इस वर्ष पहली बार कुल 23 वर्गों में सर्वाधिक अंक विजेता प्रतिभागियों में क्रमशरू ओम यादव, अमन मौर्या, रीना सिंह, हसरत अली, रमा करोलिया, विश्वनरायण श्रीवास्तव, लालू गौतम, ओम प्रकाश मौर्या, राजकुमार चौरसिया, जयकरन, सचिन कुमार गुप्ता, सचिव एलडीए, निदेशक सीमैप, रंजन प्रकाश ठाकुर, पुलिस महानिदेशक, वरिष्ठ रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, अधीक्षक जिला कारागार, गौतम बुद्धनगर, रंगोली जन शिक्षण संस्थान, अजय सिंह रायबरेली, अधीक्षक, जन भवन को एक–एक चल वैजयंती व 5100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। प्रदर्शनी में रामायण, श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने जैसे विषयों पर आधारित मॉडलों ने भारतीय संस्कृति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदर्शनी में जीवन में फल, सब्जी और फूलों के महत्व को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्णा, विशेष कार्याधिकारी (अपर मुख्य सचिव स्तर) डॉ. सुधीर महादेव बोबडे, अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बीएल मीणा सहित जनभवन एवं उद्यान विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, प्रतिभागी व कृषक बंधु उपस्थित रहे। प्राकृतिक फूलों से निर्मित आकृतियों में राजकीय विश्वविद्यालयों में छत्रपति शाहू जी महाराज विवि को भगवान श्रीकृष्ण के अधरों पर सुशोभित बांसुरी के लिए प्रथम पुरस्कार, एकेटीयू की प्रदर्शित ब्रह्मोस मिसाइल व लखनऊ विवि की ओर से निर्मित राम दरबार को द्वितीय पुरस्कार, निजी विश्वविद्यालयों में एरा विश्वविद्यालय के सारस पक्षी जोड़ा को प्रथम, कृषि तथा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों में पं. दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विवि–मथुरा की कृति गोवर्धन पर्वत को प्रथम व कृषि विश्वविद्यालय– बांदा को सुदर्शन चक्र व शंख की प्रतिकृति के लिए द्वितीय, राजकीय संस्थाओं में लखनऊ विकास प्रधिकरण की वंदेमातरम आधारित कृति, उ.प्र. आवास विकास परिषद को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित सजावट कार्य के लिए प्रथम स्थान मिला। नगर निगम, लखनऊ को रूफ टॉप गार्डिनिंग के लिए द्वितीय, राजकीय विभागों में समुद्री थीम पर समुद्री जीवों का प्रदर्शन के लिए राजकीय उद्यान लखनऊ व जय जवान के लिए मुख्य सुरक्षा अधिकारी जन भवन को द्वितीय पुरस्कार मिला। उत्तर रेलवे को नंदी व शिवलिंग के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। रक्षा उपकरणों के प्रदर्शन के लिए सेना को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी क्रम में प्रदर्शनी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्श भाग–1 क्लास–2 के वर्ग 29 में 6–हालीहाक (गमलों में जाड़े के मौसमी फूलों के पौध) के प्रदर्शन के लिए अधीक्षक जन भवन को 5100 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। स्कूली बच्चों में क्विज में प्रथम स्थान लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज की मदीहा जावेद ने, द्वितीय स्थान बाल विद्या मंदिर सी. से. स्कूल– चारबाग के मृत्युंजय मौर्य ने और तृतीय स्थान बाल विद्या मंदिर सी. से. स्कूल– चारबाग, लखनऊ की प्रियांशी सिंह ने प्राप्त किया।

संगीत साधकों के सुरों के साथ बैंड ने भरा जोश

लखनऊ, (संवाददाता)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में सोमवार शाम 'संगीत साधकों की गोष्ठी' सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। भारतीय संगीत परंपरा के विविध स्वरूपों को समर्पित यह आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लखनऊ महानगर की ओर से किया गया। इस दौरान संगीत साधकों ने सुर साधे तो वहीं बैंड ने मौजूद लोगों में जोश भरा। संगीत के माध्यम से राष्ट्र साधना, सांस्कृतिक चेतना एवं सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख जगदीश प्रसाद की मौजूदगी में भजन गायन से हुई। इस दौरान समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। गोष्ठी में संगीत के विविध स्वरूपों का प्रभावशाली समागम प्रस्तुत किया गया। गायन और वादन के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत, पाश्चात्य संगीत, भजन व कीर्तन मंडली, ऑर्केस्ट्रा पार्टी की प्रस्तुतियों के साथ ही ब्रास बैंड, मार्चिंग बैंड, स्कूल बैंड और संघ घोष की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को सांस्कृतिक रंग में रंग दिया। गोष्ठी की अध्यक्षता संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष जयंत खोत ने की। प्रख्यात ध्रुपद गायक पं. विनीत कुमार द्विवेदी, लोकगायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी और वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री विद्या विंदु सिंह के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के शारीरिक प्रमुख अखिलेश, अवध प्रांत के प्रांत प्रचारक कौशल, अवध प्रांत के घोष प्रमुख नीलकंठ, सह घोष प्रमुख संतोष, लखनऊ विभाग के विभाग प्रचारक अनिल, विभाग प्रचारक लखनऊ अमितेश जी तथा घोष प्रमुख लखनऊ अखिल आदि मौजूद रहे।

30 दिन में बुंदेलखंड विन्ध्य के हर घर पहुंचे पानी, नहीं तो एफआईआर और जेल : जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का सख्त अल्टीमेटम

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बुंदेलखंड और विन्ध्य क्षेत्र के सभी घरों तक 30 दिन के भीतर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। जल निगम (ग्रामीण) के लखनऊ स्थित कार्यालय में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने परियोजनाओं में काम कर रही कंपनियों को साफ चेतावनी दी कि तय समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होने की स्थिति में संबंधित कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और जिम्मेदार लोगों को जेल भेजा जाएगा।समीक्षा बैठक में जलशक्ति मंत्री ने बुंदेलखंड और विन्ध्य क्षेत्र में धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताते हुए बीजीसीसी और एल एंड टी जैसी कंपनियों के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हर घर नल से जल पहुंचे और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो केवल नोटिस तक बात सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी।बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में जलशक्ति मंत्री ने बताया कि बुंदेलखंड और विन्ध्य क्षेत्र की सभी परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई है। 4–5 योजनाओं को छोड़कर लगभग सभी योजनाओं का कार्य शत–प्रतिशत पूरा हो चुका है और अधिकांश गांवों में पूरी तरह जलापूर्ति शुरू कर दी गई है। हालांकि करीब तीन प्रतिशत गांव ऐसे हैं, जहां पाइपलाइन डैमेज या अन्य तकनीकी कारणों से नियमित जलापूर्ति प्रभावित हुई है। इन गांवों में तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी ग्रामीण को परेशानी न हो।जलशक्ति मंत्री ने समीक्षा बैठक में सभी जिलों के अधिशासी अभियंता और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनप्रतिनिधियों को हर स्थिति से नियमित रूप से अवगत कराएं और योजना के तहत हो रहे कार्यों की पूरी जानकारी साझा करें। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे गांवों में जाकर स्वयं ग्रामीणों से संवाद करें और मौके पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन गांवों में 100 प्रतिशत घरों में जलापूर्ति शुरू हो चुकी है, वहां 8 से 22 मार्च के बीच 'जल उत्सव' मनाया जाएगा। जलशक्ति मंत्री के निर्देश के बाद राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ने प्रदेश के करीब 22 हजार गांवों में जल उत्सव आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस आयोजन के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छ जल, जल संरक्षण और जल जीवन मिशन की उपलब्धियों से जोड़ा जाएगा।समीक्षा बैठक के दौरान जलशक्ति मंत्री ने जलापूर्ति से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 'जल सारथी' ऐप भी लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए जल जीवन मिशन से जुड़े हर गांव की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। ग्रामीण इस ऐप के माध्यम से अपने गांव में जलापूर्ति की स्थिति, परियोजना पर हुए खर्च और निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति देख सकेंगे। साथ ही संबंधित अधिकारियों के नाम और संपर्क नंबर भी ऐप पर उपलब्ध रहेंगे। जल सारथी ऐप के जरिए लोग जलापूर्ति से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे और शिकायत के समाधान के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी उन्हें इसी ऐप पर मिलती रहेगी। यह ऐप एंड्रॉयड और एप्पल दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा।बैठक में पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। जलशक्ति मंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी हाल में मार्च के अंत तक सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। अधिकारियों ने बताया कि बुंदेलखंड और विन्ध्य क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के दौरान लगभग 9,772 किलोमीटर सड़कों को काटा गया था,।

अमर पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रीड़ा दिवस

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थान अमर पब्लिक स्कूल में क्रीड़ा दिवस बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर एवं गुब्बारे उड़ाकर किया गया। इस अवसर पर राघवेंद्र शुक्ला (डीसीओ, अयोध्या), विद्यालय के चेयरमैन गिरीश कुमार पांडे, मदन मोहन त्रिपाठी (एमडी, जी.डी. गोयनका), डॉ. संजय त्रिपाठी (एमडी, कनक किड्स), निदेशक आशुतोष पांडे तथा प्रधानाचार्या आकांक्षा त्रिपाठी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत नन्हे–मुन्ने विद्यार्थियों की आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। यू.के.जी. के छात्रों ने पोम–पोम डांस, एल.के.जी. के विद्यार्थियों ने हार्मनी डांस तथा कक्षा एक के छात्रों ने जुम्बा डांस प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इसके बाद स्क्रोलिंग रेस, जलेबी रेस, बनाना रेस, बॉल कलेक्टिंग रेस, बैगपैक रेस एवं बलून ब्लास्टिंग जैसी विविध खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यालय के खेल शिक्षक चंदन शर्मा के मार्गदर्शन में विजेता विद्यार्थियों को मेडल एवं शील्ड प्रदान किए गए। खो–खो प्रतियोगिता में आकृति मौर्या और मेहताब, शतरंज प्रतियोगिता में सरगुन, लक्ष्य एवं आयुष पाल तथा बैडमिंटन प्रतियोगिता में राज यादव, अब्बास, जिगर, दिया और सुनैना ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए, जबकि अन्य प्रतिभागियों को रजत एवं कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि इसी अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन सर का जन्मदिन भी मनाया गया,जिसे विद्यालय परिवार ने केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। प्रधानाचार्या आकांक्षा त्रिपाठी ने सुंदर पंक्तियों के माध्यम से शुभकामनाएं देते हुए विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।विद्यालय की कला शिक्षिका श्रद्धा तिवारी ने सज्जा व्यवस्था में विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम का कुशल संचालन छात्रा नेहा सिंह ने किया। आयोजन को सफल बनाने में शिक्षिका स्मिता, रोजी, अंजलि, अंशिका, गरिमा, करिश्मा, मधु, जैनब, वैष्णवी, सविता, जागृति, रिचा एवं राधिका का सराहनीय सहयोग रहा। वहीं अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने में आशा पांडे, संतोष पांडे, सतीश सिंह, अजय सिंह, सुरेंद्र दुबे, अतुल पांडे और मोहर्रम अली सहित अन्य शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बोर्ड परीक्षा मे नकल रोकने के लिए पांच सचल दलों का हुआ गठन – जेडी

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।अयोध्या मंडल में इंटर व हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन,सुचारू व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय अयोध्या मंडल अयोध्या (माध्यमिक) पूर्ण रूप से तैयारी कर लिया है।इस बात की जानकारी देते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया परीक्षा को नकल विहीन करने के लिए पांच सचल दल का गठन किया गया है।बताया कि मंडल मे बोर्ड परीक्षा के दौरान एक सचल दल उनके नेतृत्व में चलेगा।बाकी अन्य चार सकल दल उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक कौस्तुभ कुमार सिंह, प्राचार्य डाइट प्रभारी धर्मेंद्र कुमार, उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं प्रभारी अयोध्या मंडल सतीश कुमार त्रिपाठी के अलावा सह जिला विद्यालय निरीक्षक अवनीश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में सचल दलों का गठन किया गया है। जिसमें पर्याप्त संख्या में अन्य सहायक कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे।मंडल में बोर्ड परीक्षा मे नकल को रोकने के लिए बोर्ड परीक्षा द्वारा जारी सभी निर्देशों का शक्ति से पालन कराया जाएगा।इस दौरान अगर कोई भी कर्मचारी या केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ विधिक कार्यवाई की जायेगी।

संक्षिप्त खबरें

शादी में जा रही महिला से 8 लाख का हार लूटा, तीन नकाबपोश बदमाश फरार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, 11 फरवरी । यूपी के जौनपुर स्थित शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार रात एक दुस्साहसिक लूट की वारदात सामने आई। भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्र में शादी समारोह में जा रही एक महिला के गले से तीन नकाबपोश बदमाशों ने सोने का हार झपट लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार निवासी अनीता सोनी मंगलवार रात करीब 10 बजे अपने घर से पांच अन्य महिलाओं के साथ हनुमानगढ़ी स्थित एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थीं। जब वे चूड़ी मोहल्ला स्थित बिस्मिल्ला मार्केट के पास पहुंचीं, तभी अपाचे बाइक पर सवार तीन नकाबपोश बदमाश अचानक उनके पास पहुंचे और उनके गले से सोने का हार झपटकर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा–तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़िता के मुताबिक, लूटा गया हार लगभग 8 लाख रुपये का बताया जा रहा है।वही इस मामले में बुधवार को जानकारी लेने पर प्रभारी निरीक्षक के.के. सिंह ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। बदमाशों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने बाजार क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने तथा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की है।

जौनपुर काशी,विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण में शामिल विकास को मिलेगी नई रफ्तार : कृपाशंकर सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,11 फरवरी। यूपी के जौनपुर में उत्तर प्रदेश में पेश 9.13 लाख करोड़ रुपये के बजट में खजाना खोलते हुए योगी सरकार ने तोहफों की बारिश कर दी जिसमें जौनपुर जिले को काशी,विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण में शामिल किया है जो जौनपुर के लिए एक उपलब्धि है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज इस प्राधिकरण के गठन की घोषणा करते हुए जौनपुर को भी इसमें शामिल करने की घोषणा की। इस कदम से जिले के विकास को गति मिलेगी। जिसको लेकर जौनपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं पूर्व गृहराज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह ने सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि अब काशी और विंध्य क्षेत्र की तर्ज पर शशिराज–ए–हिंदश जौनपुर का भी विकास सुनिश्चित होगा जिससे जौनपुर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी यह बजट गरीबों के उत्थान, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, अन्नदाताओं को सामर्थ्यवान और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आज का यह बजट ऐतिहासिक है उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 9 वर्षों में जो विकास की यात्रा बढ़ाई है उसमें यह बजट मिल का पत्थर साबित होगा।

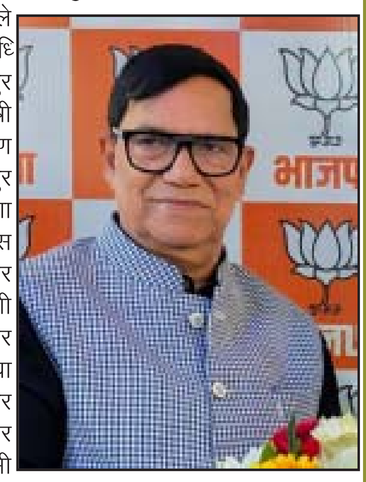

टीईटी अनिवार्यता पर जयंत चौधरी के बयान के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन, पुतला फूंका

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,11 फरवरी । यूपी के जौनपुर में टीईटी अनिवार्यता को लेकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के संसद में दिए गए बयान के विरोध में बुधवार को जनपद के शिक्षकों कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित शिक्षकों ने मंत्री के बयान को अन्यायपूर्ण बताते हुए उनका पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि संसद द्वारा 1993 में पारित एनसीटीई अधिनियम के तहत देशभर में भर्ती एवं कार्यरत लगभग 20 लाख शिक्षकों की नौकरी सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय से संकट में पड़ गई है। छह माह बीत जाने के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस कदम न उठाए जाने से शिक्षकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अरविंद शुक्ला ने कहा कि आरटीई अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीटीई के वर्ष 2017 के संशोधन ने शिक्षकों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। यदि सरकार शीघ्र समाधान नहीं निकालती है तो शिक्षक आर–पार की लड़ाई के लिए बाध्य होंगे और दिल्ली में धरना देने का निर्णय लिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने "काला कानून में संशोधन करो" और "आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त करो" जैसे नारे लगाए। इस अवसर पर लाल साहब यादव, रविचंद यादव, शिवेंद्र सिंह रानू, लक्ष्मीकांत सिंह, राजेश बहादुर सिंह 'मुन्ना', वीरेंद्र प्रताप सिंह, मनोज यादव, धर्मेंद्र यादव, विक्रम प्रकाश, सुनील, श्यामलाल मौर्य सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।

जीनोमिक्स के बाद प्रोटियोमिक्स से तय होगा जीव विज्ञान का भविष्य : डॉ. राकेश कुमार सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में बुधवार को आयोजित आमंत्रित व्याख्यान कार्यक्रम में जॉर्जिया प्रौद्योगिकी संस्थान, अटलांटा (अमेरिका) के वैज्ञानिक डॉ. राकेश कुमार सिंह ने कहा कि जीनोमिक्स के बाद प्रोटियोमिक्स ही जीव विज्ञान का भविष्य है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यह क्षेत्र रोग–निदान, औषधि–विकास, जैव–प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य अनुसंधान में निर्णायक भूमिका निभाएगा। डॉ. सिंह ने कहा कि विज्ञान और तकनीक की प्रगति अत्यंत तीव्र गति से हो रही है, इसलिए विज्ञान के विद्यार्थियों को अपने विषय के नवीनतम विकासों को गंभीरता से समझना चाहिए तथा उसी स्तर तक पहुँचने के लिए निरंतर परिश्रम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिश्रम और जागरूकता ही सफलता का मूलमंत्र है। इस अवसर पर जैव रसायन (बायोकेमिस्ट्री), जैव प्रौद्योगिकी तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान विषय के परास्नातक विद्यार्थियों ने अपनी जिज्ञासा के अनुरूप विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका डॉ. सिंह ने विस्तार से उत्तर दिया। कार्यक्रम में विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रो. राजेश शर्मा एवं कुलानुशासक प्रो. अजय प्रताप सिंह ने डॉ. राकेश कुमार सिंह का स्वागत किया।कार्यक्रम का संचालन डॉ. संजीव कुमार मौर्य ने किया। वहीं आतिफ फातिमा एवं मंजूषा सिंह ने मंच से डॉ. राकेश कुमार सिंह का जीवन–परिचय प्रस्तुत किया।अंत में डॉ. एस. पी. तिवारी ने सभी आगंतुकों एवं प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में डॉ. दिनेश कुमार, डॉ. मारुति सिंह, डॉ. सिपाही लाल, डॉ. विवेक सिंह एवं डॉ. चंद्रशेखर सिंह का विशेष सहयोग रहा।

मुठभेड़ में फरार बदमाश मोनू बघेल गिरफ्तार, पैर में लगी गोली ,पुलिस पर किया फायरिंग

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, 11 फरवरी। मीरगंज थाना क्षेत्र में बुधवार को पुलिस मुठभेड़ के बाद सरायख्वाजा थाना क्षेत्र की पूर्व मुठभेड़ में फरार चल रहे बदमाश मोनू बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुँवर अनुपम सिंह के निर्देश पर जनपद में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 10 फरवरी को सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। उस दौरान पिकअप सवार दो बदमाशों में से मो. सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि मोनू बघेल अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया था। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी प्रयागराज भागने की फिराक में है। सूचना पर मीरगंज पुलिस गोधना बाजार में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगा। पीछा करने पर वह सेमरी अंडरपास पुलिया के पास घिर गया और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसकी पहचान मोनू बघेल (23) निवासी रामनगर, थाना अखंडनगर, जनपद सुल्तानपुर के रूप में हुई है। मौके से एक तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बरामदगी के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

संक्षिप्त खबरें

छलांग के छह दिन बाद शारदा बड़ी नहर में मिला युवती का मिला शव

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।महाराजगंज थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के बाद नहर में कूदकर लापता हुई युवती का शव छह दिन बाद शारदा बड़ी नहर में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।ग्राम गोविंदपुर मजरे खानपुर निवासी सविता गौड़ उर्फ चुलबुली (20) बीते दिनों घर से नाराज होकर निकल गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसने बिल्हार घाट बड़ी नहर पुल पर अपनी चप्पल और मोबाइल रखकर नहर में छलांग लगा दी थी। आसपास मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन वह गहरे पानी में डूब गई। घटना की सूचना पर पुलिस और पीआरवी टीम मौके पर पहुंची थी और तभी से उसकी तलाश कराई जा रही थी।बुधवार सुबह ग्राम दतौली के पास शारदा बड़ी नहर में एक शव बहता दिखाई देने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। मृतका की पहचान उसके भाई उमेश ने सविता के रूप में की।थानाध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है।

कचहरी एवं स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में होगा शौचालय का निर्माण

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।स्पोर्ट्स कांप्लेक्स एवं कचहरी में शौचालय का निर्माण कराया जाएगा।इसके साथ ही सौ सफाई कर्मियों को आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।यह जानकारी महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने मीडिया को दी। उन्होंने नगर निगम कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई संभव की अध्यक्षता की।इस दौरान आईं 20 में 12 समस्याओं का समाधान कराया। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने सड़क, इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण से जुड़ी आठ मांगों को जांच के लिए निर्माण विभाग को सौंपा।महापौर ने अधिकारियों से कहा कि जन समस्याओं का निदान प्राथमिकता से करें। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडेय ने बताया कि इस मौके पर पार्षद अनूप श्रीवास्तव ने नरेंद्रदेव वार्ड में सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता जताई। राकेश मिश्र ने अवैद्यनाथ वार्ड के श्रीरामपुरम कॉलोनी में सड़क एवं नाली निर्माण, सुनील पांडेय ने दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में नाली निर्माण की मांग की।करम अलीपुरवा निवासी दुर्गावती मौर्य ने जलकर एवं गृह कर का जनरल सर्वे कराने, नियावां के वसीम ने कर ज्यादा आने की शिकायत की।इस मौके पर पार्षद जयनारायण सिंह रिंकू, अनुज दास, अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, भारत भार्गव, सुमित कुमार, मुख्य अभियंता सिविल पुनीत कुमार ओझा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरएम शुक्ल, महाप्रबंधक जलकल सौरभ श्रीवास्तव, कर निर्धारण अधिकारी विनय प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।बताया कि 12 फरवरी को अयोध्या में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 के लिए मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। मंगलम गेस्ट में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी सुबह 11रू00 बजे नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार की मौजूदगी में करेंगे। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडेय ने बताया कि मंडल स्तरीय कार्यशाला में अपर निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ऋतु सुहास की अगुवाई में पांच सदस्यीय दल नगर निकाय से जुड़े 110 अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों में मंडल के सभी पांचों जिलों के अपर जिलाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक स्वच्छ भारत मिशन, क्षेत्रीय प्रबंधक वैभव पांडे, सभी नगर पंचायत एवं नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी शामिल होंगे।व्यवस्था की जिम्मेदारी अपर नगर आयुक्त भारत भार्गव एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरएम शुक्ल के ऊपर होगी।

कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर देकर बचाई जा सकती है मरीज की जान - डॉ गौरव श्रीवास्तव

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।कोरोना के बाद से हार्ट अटैक के मामलों में काफी वृद्धि हुई है।अटैक के दौरान अगर समय रहते मरीज को नजदीकी व हृदय रोग विशेषज्ञ के नही ले जाया गया तो उसकी मौत भी सकती हैं।यह बातें शहर के माने जाने चिकित्सक डॉ गौरव श्रीवास्तव ने बताई।बताया कि अगर मरीज को हार्ट अटैक आये तो उसके के लिए पहला तीन मिनट गोल्डन समय है।डॉ गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि आजकल व्यायाम और शादी विवाह मे नृत्य करते समय, आफिस व अन्य जगहों पर लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है।इसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है।ऐसे समय में सीपीआर देने चाहिए। इसके लिए सीपीआर की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को होनी चाहिए।बताया कि कार्डियक अरेस्ट के मरीज के लिए पहला तीन मिनट गोल्डन टाइम होता है।अगर नौ मिनट तक मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिले तो व्यक्ति ब्रेन डेथ का शिकार हो सकता है।उस समय मरीज को सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) दिया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है।बताया कि सीपीआर एक मेडिकल थेरेपी की तरह है।इससे हार्ट अटैक आने पर मरीज को सीपीआर देते हुए अस्पताल पहुंचाया जाता है।सीपीआर तब तक देते रहना चाहिए जब तक एंबुलेंस न आ जाए या मरीज अस्पताल या विशेषज्ञ चिकित्सक के पास नहीं पहुंच जाए।ऐसा करने से मरीज के बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।उन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति की सांस सा धड़कन रुक गई है तो ऑक्सीजन की कमी से शरीर की कोशिकाएं बहुत जल्द खत्म होने लगी है। इसका असर मस्तिष्क पर भी पड़ता है।सही समय पर सीपीआर और इलाज शुरू नहीं होने पर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है।इस विधि से व्यक्ति की सांस वापस लाने तक या दिल की धड़कन सामान्य हो जाने तक छाती को विशेष तरीके से दबाया जाता है।बताया कि सीपीआर के लिए सबसे पहले पीड़ित को किसी ठोस जगह पर लिटा दिया जाता है और प्राथमिक उपचार देने वाला व्यक्ति उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है।उसकी नाक और गला चेक कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसे सांस लेने में कोई रुकावट तो नहीं है।इसके बाद अपने दोनों हाथों की मदद से विशेष तरीके से एक मिनट में 100 से 120 बार छाती के बीच में तेजी से दबाना होता है।हर एक पुश के बाद छाती को वापस अपनी सामान्य स्थिति में आने देना चाहिए।इससे शरीर में पहले से मौजूद रक्त को हृदय पंप करने लगता है।30 बार पुश करने के बाद मुंह पर साफ रूमाल रखकर दो बार सांसें दी जाती हैं।इससे शरीर में रक्त का प्रवाह शुरू होता है और मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलने लगती है।बताया कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) एक आपातकालीन प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की सांस या दिल के रुकने पर उसकी जान बचाने में मदद कर सकती है। जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद कर देता है, तो उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डिएक अरेस्ट के दौरान हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ों सहित शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त पंप नहीं कर सकता है। इस दौरान इलाज नहीं मिलने पर मिनटों में ही व्यक्ति की मौत हो सकती है।उन्होंने बताया कि जब दिल तक खून पहुंचना बंद होने की स्थिति को हार्ट अटैक कहा जाता है। दरअसल, कोलेस्ट्रॉल और फैट के कारण अक्सर दिल तक खून ले जाने वाली धमनी में खून का प्रवाह रुक जाता है और इसके कारण दिल तक खून नहीं पहुंच पाता है।धमनी ब्लॉक होने की वजह से ऑक्सीजन भी इस तक नहीं पहुंच पाती है।हालांकि ऐसी स्थिति में दिल की कार्यप्रणाली बरकरार रहती है यानी कि इंसान का दिल धड़कना बंद नहीं होता है। बताया कि कार्डियक अरेस्ट उस स्थिति में होता है जब कार्डियक कार्यप्रणाली अचानक रुक जाती है यानी दिल धड़कना बंद कर देता है। इस दौरान फेफड़ों, दिमाग और अन्य महत्वपूर्ण अंगों तक खून पहुंचना रुक जाता है और प्रभावित व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। कई बार हार्ट अटैक आने की वजह से भी अचानक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है।ऐसी इमरजेंसी में मरीज को सीपीआर और डिफाइब्रिलेटर से बिजली के झटके दिए जाते हैं।जिससे मरीज की जान बच सके।

यूपी बजट पर सियासत तेज विपक्ष ने बताया चुनावी, भाजपा ने कहा समावेशी विकास का दस्तावेज

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

यूपी के जौनपुर से बजट पर लोगो की राय जाना हिंदुस्थान समाचार प्रतिनिधि ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को अपना दसवां बजट पेश किया, जिसके बाद प्रदेश सहित जौनपुर में भी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। विपक्षी दलों ने बजट को चुनावी और जनविरोधी बताया, जबकि भाजपा ने इसे सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास का दस्तावेज करार दिया। विपक्ष का आरोप है कि बजट में जौनपुर जिले को कोई विशेष परियोजना नहीं मिली। जिले में सत्तापक्ष के चार विधायक, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव तथा राज्यसभा सदस्य सीमा देवी की मौजूदगी के बावजूद स्थानीय स्तर पर बड़ी घोषणा न होने से लोगों में निराशा है। बजट पर बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने बजट को जनविरोधी बताते हुए कहा कि यह केवल कागजी और चुनावी बजट है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों, युवाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ छल किया गया है। फसल लागत, सिंचाई, खाद–बीज, कर्जमाफी और स्थायी रोजगार सृजन को लेकर कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम जरूरत की वस्तुएं लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। उन्होंने सरकार से सब्सिडी और प्रत्यक्ष सहायता बढ़ाने की मांग की। उनका आरोप है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, रोजगार और गरीब वर्ग के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं। बसपा जिलाध्यक्ष संग्राम भारती ने भी बजट को जनहित के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, गरीबी उन्मूलन और युवाओं, महिलाओं व किसानों के हित में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने बजट का बचाव करते हुए कहा कि यह प्रदेश के समग्र विकास का खाका है। सड़क, आरओबी और फ्लाईओवर निर्माण के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया है, जिसका लाभ जौनपुर को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि मेधावी छात्र–छात्राओं, किसानों और युवाओं के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। प्रदेशभर में गर्ल्स हॉस्टल निर्माण की घोषणा के तहत जौनपुर में भी छात्रावास बनाया जाएगा, जिससे बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जहां विपक्ष इसे आंकड़ों और घोषणाओं तक सीमित बता रहा है, वहीं सत्तापक्ष इसे विकासोन्मुख और दूरदर्शी बजट बता रहा है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।